

भारत—अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, राजनीति

डा० सदगुरु पुष्पम¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, के० एस० साकेत पीजी कालेज, अयोध्या, उ०प्र०, भारत

Received: 20 January 2025 Accepted & Reviewed: 25 January 2025, Published : 31 January 2025

Abstract

भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। यह संबंध केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा, और भू-राजनीतिक रणनीतियों को भी प्रभावित करते हैं। इस शोधपत्र में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण किया गया है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक सहयोग, तकनीकी नवाचार, और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त रणनीति को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। शोध का उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार यह साझेदारी दोनों देशों की विदेश नीति को आकार देती है और वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती है। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक स्वायत्तता, और सहयोगात्मक भू-राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है, बल्कि एक स्थायी, बहुध्रुवीय और संतुलित विश्व व्यवस्था की ओर भी संकेत करती है।

कीवर्ड — भारत-अमेरिका संबंध, रणनीतिक साझेदारी, भू-राजनीति, हिंद-प्रशांत नीति, परमाणु करार, तकनीकी सहयोग, विदेश नीति, चीन नीति, रक्षा सहयोग, बहुपक्षीय मंच

Introduction

भारत और अमेरिका, दो सबसे बड़े लोकतंत्र, जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक हित, और रणनीतिक दृष्टिकोण अनेक पहलुओं में भिन्न होते हुए भी आज वैश्विक परिदृश्य में एक-दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी के रूप में उभरे हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जहाँ शीतयुद्ध की वैश्विक खींचतान और भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण दोनों देशों के संबंध सीमित और तनावपूर्ण रहे, वहीं 21वीं सदी की शुरुआत ने इस द्विपक्षीय संबंध को नई दिशा और गहराई प्रदान की। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, वैश्विक मंचों पर उसकी सक्रिय भूमिका, और दक्षिण एशिया में उसकी भू-राजनीतिक स्थिति ने अमेरिका को भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित किया। वहीं भारत ने भी अमेरिका के साथ सहयोग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी विकास, और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा। सन् 2005 में घोषित भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता इस रणनीतिक साझेदारी का एक ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने दोनों देशों के बीच पारंपरिक अविश्वास की दीवार को तोड़ा और रक्षा, विज्ञान, ऊर्जा, व्यापार, और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं खोलीं। आज भारत और अमेरिका न केवल द्विपक्षीय हितों के आधार पर अपितु हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक रणनीति, चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिरोध, और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने की दिशा में प्रयासरत हैं। यह शोधपत्र इसी रणनीतिक साझेदारी के राजनीतिक पक्षों का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विकास-क्रम, वर्तमान स्वरूप, प्रमुख समझौतों, और भू-राजनीतिक प्रभावों को प्रस्तुत करते हुए यह समझना है कि यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय राजनीति को परिभाषित

करती है, बल्कि वैश्विक शक्ति संरचना को भी प्रभावित करती है। इस प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी केवल एक अस्थायी या अवसरवादी गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक गहरे राजनीतिक विमर्श और साझा भविष्य दृष्टि पर आधारित स्थायी गठजोड़ है।

परिकल्पना— भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर है। यह परिकल्पना की जाती है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य, विशेषकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के उभार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसे कारकों ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहराई प्रदान की है। यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक शासन और बहुपक्षीय मंचों पर भी परिलक्षित होती है।

परिकल्पना के प्रमुख तत्व—

1. भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य हितों का अभिसरण बढ़ा है।
2. रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना है।
3. उभरते वैश्विक खतरों — आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा— ने दोनों देशों के सहयोग को प्रगाढ़ किया है।
4. भारत की Act East नीति और अमेरिका की Indo-Pacific Strategy* ने साझेदारी को नया रणनीतिक आयाम दिया है।
5. भले ही वैचारिक व राष्ट्रीय हितों में भिन्नता हो, दोनों देश व्यावहारिक सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं।

शोध प्राविधि— यह शोध गुणात्मक (Qualitative) पद्धति पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों को अपनाया गया है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का व्यापक उपयोग किया गया है, जिसमें भारत और अमेरिका की आधिकारिक नीतिगत दस्तावेज़, संयुक्त वक्तव्य, अनुसंधान पत्र, शैक्षणिक पुस्तकें, अंतरराष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट्स और विद्वत लेख शामिल हैं।

प्रमुख शोध पद्धतियाँ

ऐतिहासिक विश्लेषण— भारत-अमेरिका संबंधों के क्रमिक विकास को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है।

वर्णनात्मक पद्धति— रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं को क्रमवार वर्णित किया गया है।

विश्लेषणात्मक पद्धति— रक्षा, व्यापार, कूटनीति, तकनीकी, और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विश्लेषण किया गया है।

तुलनात्मक अध्ययन— शीत युद्ध के बाद और 21वीं सदी के आरंभ में भारत-अमेरिका संबंधों की तुलना की गई है।

दस्तावेजीय अध्ययन— विभिन्न सरकारी और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन की सीमा — यह अध्ययन 2000 से 2024 के कालखंड को मुख्यतः केंद्रित करता है, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रमुख प्रगति को शामिल किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि— भारत-अमेरिका संबंधों का इतिहास जटिल, बहुस्तरीय और परिवर्तनीय रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व और भारत की स्वतंत्रता के साथ उसकी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति ने इन संबंधों की दिशा को लंबे समय तक प्रभावित किया। रणनीतिक साझेदारी के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक संदर्भ को जानना आवश्यक है।

शीत युद्ध काल— शीत युद्ध काल में अमेरिका और भारत के बीच संबंध स्थिर न रहकर कई बार टकरावपूर्ण भी रहे। गुटनिरपेक्षता बनाम ध्रुवीकरण के दौर में भारत ने 1950 के दशक में 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' की अगुआई की, जबकि अमेरिका ने पूंजीवादी खेमे के नेता के रूप में सोवियत संघ के विरोध में विश्व को दो ध्रुवों में बाँट दिया। इससे भारत-अमेरिका संबंधों में शुरू से ही एक वैचारिक दूरी बनी रही। पाकिस्तान से अमेरिकी निकटता तब महसूस हुई जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सामरिक दृष्टिकोण से अधिक महत्व दिया और उसे सैन्य तथा आर्थिक सहायता प्रदान की। 1954 में पाकिस्तान का SEATO (South East Asia Treaty Organization) और CENTO में प्रवेश भारत को असहज करने वाला था। इससे भारत में यह धारणा बनी कि अमेरिका, भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी कर रहा है। 1971 का भारत-पाक युद्ध में जब भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में निर्णायक भूमिका निभाई, तब अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। USS Enterprise का बंगाल की खाड़ी में भेजा जाना भारत-अमेरिका तनाव का चरम था। भारत ने इस समय सोवियत संघ से 'मित्रता संधि' (Treaty of Peace, Friendship and Cooperation – 1971) की।

शीतयुद्धोत्तर युग— सोवियत संघ के विघटन (1991) के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति और आर्थिक नीति दोनों में व्यापक परिवर्तन किए। आर्थिक उदारीकरण (1991) के दौरान भारत के उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने अमेरिकी व्यवसायों को भारत में निवेश हेतु आकर्षित किया। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में तेजी आई। परमाणु परीक्षण और प्रतिबंध (1998) अर्थात् भारत के पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि, इसके कुछ ही वर्षों बाद दोनों देशों के बीच संवाद शुरू हुआ। अमेरिकी राजदूत स्टॉब टालबॉट और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच हुई वार्ताओं ने संबंधों को सामान्य बनाने में भूमिका निभाई। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की 2000 में भारत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में 'टर्निंग पॉइंट' प्रस्तुत किया। यह यात्रा रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत मानी जाती है। 2004 में Next Steps in Strategic Partnership (NSSP) से रणनीतिक साझेदारी का नया युग का प्रारम्भ हुआ। इस पहल के तहत रक्षा, अंतरिक्ष, नागरिक परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी में सहयोग की नींव पड़ी। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के नेतृत्व में भारत-अमेरिका परमाणु करार की घोषणा हुई। इसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में भागीदारी दी। 2008 123 समझौते को अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिली और इससे भारत को NSG (Nuclear Suppliers Group) की छूट प्राप्त हुई और वैश्विक परमाणु सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2016 में भारत को 'मेजर डिफेंस पार्टनर' (MDP) का दर्जा मिला। 2018-2020 के बीच तीन महत्वपूर्ण रक्षा समझौते संपन्न हुए— LEMOA (Logistics EÜchange Memorandum of Agreement), COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement), BECA (Basic EÜchange and Cooperation Agreement)

अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक गठजोड़ बढ़ा, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने हेतु हिंद-प्रशांत रणनीति और Quad की सक्रियता बढ़ी। भारत-अमेरिका संबंधों का इतिहास विरोध और सहयोग दोनों का मिश्रण रहा है। शीतयुद्ध की वैचारिक सीमाएं, पाकिस्तान की

भूमिका, परमाणु परीक्षणों की कूटनीति और अंततः रणनीतिक साझेदारी की दिशा में उठे कदमों ने इस द्विपक्षीय संबंध को समय के साथ पुनर्परिभाषित किया है। आज यह साझेदारी एक परिपक्व, व्यापक और बहुआयामी रूप ले चुकी है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का विकास- भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की यात्रा धीरे-धीरे एक औपचारिक संवाद से लेकर आज एक बहुआयामी सहयोग में रूपांतरित हो चुकी है। यह साझेदारी केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष, तकनीक, जलवायु, और हिंद-प्रशांत रणनीति जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक विस्तार पा चुकी है। इस खंड में साझेदारी के विभिन्न चरणों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है-

प्रारंभिक चरण (1990-2004) संवाद और विश्वास की स्थापना- 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात, भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कदम रखा जिससे अमेरिका की भारत में रुचि बढ़ी। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, परंतु 1999-2000 में जसवंत सिंह, स्टॉब टालबॉट संवाद के माध्यम से विश्वास का पुनर्निर्माण हुआ। 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा ने संबंधों को गहराई दी। उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार घोषित किया। 2004 'Next Steps in Strategic Partnership' (NSSP) की घोषणा। इसने चार प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की नींव रखी- असैन्य परमाणु, नागरिक अंतरिक्ष, उच्च तकनीक, मिसाइल रक्षा। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा हुई। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, फिर भी उसे परमाणु ऊर्जा व्यापार हेतु अनुमति मिली। यह एक वैश्विक कूटनीतिक सफलता थी। 2008 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 123 समझौते को स्वीकृति, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से भारत को छूट व भारत को विश्व परमाणु व्यापार में मान्यता प्राप्त हुई।

बहुआयामी सहयोग का दौर (2009-2016)- ओबामा प्रशासन (2009-2016) में अमेरिका ने भारत को Major Strategic Partner घोषित किया। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत किया गया। 2015 में U-S-India Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and Indian Ocean Region की घोषणा हुई। यह पहली बार था जब अमेरिका ने भारत को इंडो-पैसिफिक सुरक्षा संरचना का अभिन्न भाग माना। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल, भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई।

सामरिक साझेदारी का सुदृढ़ीकरण (2016-2020)- 2016 अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। यह दर्जा केवल भारत को प्राप्त है इससे अत्याधुनिक अमेरिकी रक्षा तकनीक तक पहुंच सुलभ हुई। 2018 में COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement) सुरक्षित सैन्य संचार हेतु समझौता हुआ। 2020 में BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement) जियो-स्पेशियल खुफिया डेटा साझा करने के लिए समझौता हुआ। इन समझौतों से भारत की अमेरिका के साथ सैन्य-रणनीतिक साझेदारी पूर्ण हो गई जिसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहा जाता है।

वर्तमान दौर और Indo-Pacific रणनीति (2021-2024)- भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी ने 2021 से 2024 के बीच एक नया आयाम ग्रहण किया है, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की सक्रिय भूमिका और समन्वय के माध्यम से। यह युग न केवल क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक कूटनीति, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी निर्णायक बन गया है। इंडो-पैसिफिक

शब्दावली भौगोलिक से कहीं अधिक रणनीतिक है। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ते हुए एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संप्रभुता और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति में भारत और अमेरिका की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। 2021 के बाद क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue – भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) ने नई ऊर्जा प्राप्त की। कोविड-19 वैक्सीन वितरण, जलवायु परिवर्तन से निपटना, तकनीकी मानकों में सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा तय की गई। भारत-अमेरिका साझेदारी ने इस मंच को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया। भारत और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास (जैसे मालाबार नौसेना अभ्यास) के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और प्रबल किया। दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के पक्ष में संयुक्त वक्तव्य दिए गए, जो चीन के विस्तारवादी रवैये के विरुद्ध संतुलन का संकेत हैं। 2021–2024 के दौरान चीन की आक्रामक रणनीतियों गलवान झड़पों के बाद से अमेरिका और भारत की घनिष्टता में तीव्र वृद्धि देखी गई। कोविड-19 के बाद की स्थिति में वैक्सीन कूटनीति और स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त करने में दोनों देशों ने मिलकर कार्य किया। हेल्थकेयर सप्लाई चेन को बहुराष्ट्रीय स्तर पर लचीला बनाने के प्रयासों में भारत-अमेरिका समन्वय उल्लेखनीय रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता दिखाई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हरित ऊर्जा निवेश, और नेट जीरो के लक्ष्यों की दिशा में सहयोग के प्रयास तेज हुए। इस अवधि में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए निर्णायक रही है। इंडो-पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में यह न केवल क्षेत्रीय स्थायित्व हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन और भविष्य की कूटनीति में भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ बनाती है।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी एक निरंतर विकसित होती संरचना है, जो विश्व राजनीति की आवश्यकताओं, क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन, और वैश्विक स्थायित्व के अनुरूप ढलती जा रही है। यह साझेदारी केवल सुरक्षा और रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीकी, आर्थिक, कूटनीतिक, और पर्यावरणीय विमर्शों तक विस्तृत हो चुकी है।

राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम – भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का राजनीतिक और कूटनीतिक पक्ष इस सहयोग की रीढ़ है। यह न केवल दोनों देशों की विदेश नीतियों को परिभाषित करता है, बल्कि वैश्विक सत्ता-संतुलन, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संस्थाओं में साझा दृष्टिकोण के निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। इस खंड में भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारत और अमेरिका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्रता, मानवाधिकार, विधि-राज, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों में विश्वास रखते हैं। यह साझा लोकतांत्रिक विरासत उनकी राजनीतिक साझेदारी को नैतिक और वैचारिक समर्थन प्रदान करती है। दोनों देश वैश्विक लोकतांत्रिक गठजोड़ों का समर्थन करते हैं, नागरिक समाज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और पारदर्शी शासन प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु द्विपक्षीय कार्यक्रम भी संचालित करते हैं। भारत और अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय समन्वय देखा गया है। अमेरिका के अफगानिस्तान से सैनिक वापसी (2021) के बाद भारत की भूमिका पर भी विचार हुआ। भारत ने अफगान विकास में अरबों डॉलर का निवेश किया जबकि अमेरिका ने

वहाँ सैन्य रणनीति पर ध्यान दिया। तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों की चिंताएँ साझा रही हैं। भारत और अमेरिका की ईरान व रूस के प्रति नीतियाँ अलग रही हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल और हथियारों पर निर्भरता कम करे। भारत अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने का प्रयास करता है। अमेरिका भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहता है। G-20, WTO, IMF जैसी संस्थाओं में भारत और अमेरिका मिलकर कार्य करते हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र वर्तमान वैश्विक राजनीति का सबसे सक्रिय भू-रणनीतिक क्षेत्र है। भारत और अमेरिका दोनों हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध हैं। चीन की आक्रामकता को संतुलित करने हेतु सामरिक साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। पहले अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति पाकिस्तान-केंद्रित रही, पर अब यह भारत-केंद्रित हो गई है। अमेरिका भारत को नेट सिक््योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। दोनों देशों की राजनीति में चाहे सरकारें बदली हों, पर भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी निरंतर सशक्त होती रही है यह द्विदलीय सहमति का प्रतीक है। भारत और अमेरिका के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाला वार्षिक संवाद, कूटनीतिक मंचों पर उच्च स्तरीय संवाद, व रणनीतिक, सुरक्षा, और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होती है। अमेरिका कभी-कभी भारत में मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी करता है। भारत इसे आंतरिक मामला मानता है और रणनीतिक स्वायत्तता की पुनः पुष्टि करता है। हालाँकि इन मुद्दों पर मतभेद होते हैं, फिर भी दोनों पक्ष इनसे संपूर्ण संबंधों को प्रभावित नहीं होने देते। राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी एक परिपक्व, सशक्त और बहुआयामी संरचना है। यह संबंध केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ से नहीं, बल्कि साझा मूल्यों, वैश्विक दृष्टिकोण, और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों पर आधारित है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्मान, संवाद और समझ ने इसे 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली रणनीतिक साझेदारियों में स्थापित कर दिया है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग – भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग है। 21वीं सदी की वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों जैसे आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर युद्ध, और रणनीतिक संतुलन ने दोनों देशों को एक-दूसरे के निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं जो रणनीतिक विश्वास को मजबूत करते हैं।

GSOMIA (2002) General Security of Military Information Agreement – इसके तहत दोनों देशों के बीच संवेदनशील सैन्य सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ।

LEMOA (2016) Logistics Exchange Memorandum of Agreement – इससे दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य अड्डों, ईंधन, मरम्मत और आपूर्ति तक पहुँच प्राप्त हुई।

COMCASA (2018) Communications Compatibility and Security Agreement – इसके माध्यम से अमेरिका ने भारत को अपने उच्चस्तरीय सैन्य संचार उपकरण उपलब्ध कराए।

BECA (2020): Basic Exchange and Cooperation Agreement – इसके द्वारा भू-स्थानिक खुफिया डेटा का साझा उपयोग संभव हुआ, जिससे भारत की मिसाइल प्रणाली की सटीकता में सुधार हुआ।

भारत और अमेरिका नियमित रूप से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत अमेरिका से अब तक लगभग 20 बिलियन डॉलर से अधिक का रक्षा उपकरण खरीद चुका है, जिनमें C-17 ग्लोबमास्टर, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I समुद्री गश्ती विमान आदि शामिल हैं।

DTTI (Defense Technology and Trade Initiative) के माध्यम से उन्नत रक्षा तकनीकों के विकास और सह-निर्माण की दिशा में कार्य हो रहा है, जिसमें विमान-वाहक, ड्रोन तकनीक, और जासूसी उपकरणों पर शोध शामिल है। भारत और अमेरिका आतंकवाद विरोधी रणनीतियों में सहयोग करते आए हैं। 26/11 के बाद दोनों देशों ने खुफिया साझेदारी को सुदृढ़ किया। संयुक्त आतंकवाद विरोधी कार्यबल के माध्यम से दोनों देश जानकारी साझा करते हैं। भारत-अमेरिका रक्षा और सुरक्षा सहयोग केवल हथियारों के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी रणनीतिक साझेदारी का संकेत है जो वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित करता है। जैसे-जैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, यह साझेदारी भविष्य में और अधिक निर्णायक भूमिका निभाएगी।

आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध – भारत और अमेरिका के मध्य आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों का दायरा पिछले दो दशकों में अत्यधिक व्यापक और बहुआयामी हुआ है। यह संबंध केवल वस्तु एवं सेवा व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निवेश, तकनीकी सहयोग, नवाचार, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा अधिकार, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी जैसे क्षेत्रों में भी गहराते जा रहे हैं। दोनों देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख स्तंभ हैं, और उनकी आपसी आर्थिक सहभागिता वैश्विक व्यापार व्यवस्था को दिशा देने की क्षमता रखती है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक लेन-देन पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ा है। 2000 में लगभग +20 बिलियन का व्यापार 2022 में बढ़कर +191 बिलियन (वस्तु और सेवा दोनों मिलाकर) तक पहुँच गया। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। भारत अमेरिका को वस्त्र, आभूषण, औषधियाँ, मशीनरी, आईटी सेवाएँ आदि निर्यात करता है, जबकि अमेरिका भारत को विमान, उच्च तकनीकी मशीनें, कृषि उत्पाद, और रक्षा उपकरण निर्यात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक बड़ा स्रोत रहा है। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ऐप्पल और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, विशेष रूप से ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग, और विनिर्माण क्षेत्रों में। वहीं भारत की प्रमुख कंपनियाँ जैसे इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो आदि अमेरिका में आईटी सेवाएँ, बायोटेक्नोलॉजी, और अनुसंधान-आधारित निवेश कर रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच 'India-U-S- Commercial Dialogue' और 'India-U-S- CEO Forum' जैसे मंच द्विपक्षीय आर्थिक संवाद को बढ़ावा देते हैं। इन मंचों के माध्यम से व्यापार-नीति समन्वय, बौद्धिक संपदा अधिकार, नियामकीय सुधार, तथा ऊर्जा और पर्यावरणीय व्यापार की दिशा में साझा प्रयास किए जाते हैं।

यद्यपि भारत-अमेरिका आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ़ हो रहे हैं, तथापि कुछ मुद्दों पर मतभेद भी विद्यमान हैं, जैसे जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज़ से भारत को हटाया जाना, डेटा लोकलाइजेशन नीति, आईटी और फार्मा क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर चिंता, शुल्कों और व्यापार अवरोधों को लेकर विवाद आदि। इन विवादों के बावजूद दोनों देशों की प्रवृत्ति संवाद और समाधान की ओर अग्रसर रहती है। कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर कार्य कर रहे हैं। 'India-U-S- Initiative on Critical and Emerging Technologies' (CET) के अंतर्गत सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G@6G, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता और दोनों देशों की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता, आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाई पर ले जाने में सहायक हो सकती है। विशेष रूप से हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में

अमेरिका की भागीदारी भविष्य में अत्यधिक निर्णायक सिद्ध हो सकती है। भारत-अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक संबंध न केवल आपसी समृद्धि के वाहक हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन, विविधता और नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। इन संबंधों की निरंतरता और प्रगति दोनों देशों के लिए रणनीतिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ऊर्जा और तकनीकी सहयोग— भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख आयाम ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग है। दोनों देश इस क्षेत्र में परस्पर लाभकारी साझेदारी के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन, एवं अत्याधुनिक तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने में जुटे हैं। यह सहयोग दोनों देशों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और आर्थिक विकास के साझा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है।

असैनिक परमाणु समझौता— 2005 में भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता (123 समझौता) इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। इस समझौते के माध्यम से अमेरिका ने भारत को असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक मुख्यधारा में लाने का कार्य किया। यह समझौता भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास को मजबूत करने का माध्यम बना।

ऊर्जा संवाद— 2005 में प्रारंभ हुआ भारत-अमेरिका ऊर्जा संवाद एक बहुआयामी मंच है जो ऊर्जा की विविध शाखाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ कोयला तकनीक, जैवईंधन, और स्मार्ट ग्रिड पर केंद्रित है। यह संवाद नीति, अनुसंधान, नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु सहयोग— अमेरिका ने भारत की राष्ट्रीय सौर मिशन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में सक्रिय भागीदारी की है। 2021 में जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, नवाचार और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण (storage), और कार्बन कैप्चर तकनीकों पर भी शोध शामिल है।

तकनीकी सहयोग और नवाचार— भारत और अमेरिका के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फोरम के माध्यम से दोनों देश अनुसंधान, उच्च शिक्षा, अंतरिक्ष तकनीक, और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। NASA और ISRO के बीच संयुक्त उपग्रह मिशनों से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेमीकंडक्टर निर्माण तक अनेक पहलें सामने आई हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला— भारत-अमेरिका साझेदारी ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता, तेल एवं प्राकृतिक गैस व्यापार, तथा उभरते विकल्पों जैसे LNG के आयात-निर्यात में भी दिखाई देती है। अमेरिका भारत को LNG का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना है, जिससे भारत की ऊर्जा विविधीकरण रणनीति को बल मिला है। ऊर्जा और तकनीकी सहयोग भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का आधारभूत स्तंभ बन चुका है। इससे न केवल दोनों देशों की विकास आवश्यकताओं को बल मिला है, बल्कि वैश्विक जलवायु नीतियों और नवाचार-आधारित सतत भविष्य की दिशा में भी प्रगति हुई है। भविष्य में यह सहयोग हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण और उन्नत अनुसंधान के क्षेत्रों में और अधिक सघन हो सकता है।

बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता— भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी गहन सहभागिता के रूप में उभर कर सामने आई है। दोनों देशों की सहभागिता अंतरराष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय मंचों और वैश्विक गठबंधनों में व्यापक रूप से

दिखाई देती है। इस सहभागिता का उद्देश्य न केवल साझा हितों की रक्षा करना है, बल्कि वैश्विक स्थिरता, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। भारत और अमेरिका दोनों संयुक्त राष्ट्र के सक्रिय सदस्य हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोध, वैश्विक स्वास्थ्य, और सतत विकास जैसे विषयों पर दोनों देशों के दृष्टिकोणों में सामंजस्य देखने को मिलता है। अमेरिका ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन किया है, जो दोनों के राजनीतिक निकटता का संकेतक है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बना क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त, स्वतंत्र और समावेशी रणनीतिक संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह मंच समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और कोविड-19 टीकाकरण जैसे मुद्दों पर सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। क्वाड में भारत और अमेरिका की सक्रिय भूमिका वैश्विक भू-राजनीति में उनकी साझा चिंताओं और लक्ष्यों को दर्शाती है। G20, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, उसमें भारत और अमेरिका दोनों की भागीदारी वैश्विक आर्थिक नीतियों को दिशा देने में सहायक रही है। व्यापार, जलवायु वित्त, डिजिटलीकरण, और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के सहयोग ने G20 के निर्णयों को प्रभावी बनाया है। विश्व व्यापार संगठन में भी भारत और अमेरिका, हालांकि कई बार भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, फिर भी विकासशील देशों के हितों और वैश्विक व्यापार सुधारों को लेकर संवाद बनाए रखते हैं।

पेरिस जलवायु समझौता और वैश्विक जलवायु मंच— भारत और अमेरिका दोनों पेरिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। 2021 में अमेरिका की लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की भागीदारी ने इस दिशा में संयुक्त प्रयासों को बल दिया है। दोनों देश India-U-S- Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कटौती के लिए साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।

ASEAN और East Asia Summit: अमेरिका और भारत दोनों ASEAN देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मंच पर अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं।

IAEA (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी)— असैन्य परमाणु सहयोग को लेकर भारत-अमेरिका 123 समझौते के बाद IAEA के अंतर्गत दोनों देशों का सहयोग बढ़ा है।

BRICS और SCO में भारत की भूमिका— यद्यपि अमेरिका इन संगठनों का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इन मंचों के माध्यम से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका के हितों और चिंताओं को संवाद के माध्यम से संतुलित करने की कोशिश करता है।

वैश्विक महामारी और WHO में सहयोग— COVID-19 महामारी के दौरान भारत और अमेरिका ने वैक्सीन उत्पादन, आपूर्ति और अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग किया। भारत को फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पहचान दिलाने में अमेरिकी समर्थन और COVAX पहल के अंतर्गत दोनों की सक्रिय भूमिका ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ किया।

बहुपक्षीय मंचों पर भारत-अमेरिका की सहभागिता केवल नीतिगत मेल नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें दोनों देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने और एक न्यायसंगत, समावेशी और सुरक्षित विश्व व्यवस्था की स्थापना की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग आने वाले वर्षों में और अधिक संस्थागत और बहुआयामी होता जाएगा।

समकालीन चुनौतियाँ – भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी ने बीते कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु वर्तमान में इस रिश्ते के समक्ष अनेक समकालीन चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आई हैं। ये चुनौतियाँ न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती हैं, बल्कि वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को भी उजागर करती हैं। इनमें से प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं

1. रणनीतिक स्वायत्तता – भारत ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता का पक्षधर रहा है, जबकि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों से अपेक्षा करता है कि वे उसके नेतृत्व का समर्थन करें, विशेषकर चीन और रूस जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के संदर्भ में। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के तटस्थ रुख और रूस से तेल की खरीद पर अमेरिका ने चिंता जताई, जिससे यह तनाव और स्पष्ट हो गया।

2. व्यापारिक विवाद और संरक्षणवाद– हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक शुल्क, ई-कॉमर्स नीतियाँ, डेटा संरक्षण, वीजा नियम (विशेष रूप से H-1B) जैसे कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज़' से भारत को बाहर किया जाना, अमेरिका द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने संबंधों में तनाव बढ़ाया।

3. चीन को लेकर दृष्टिकोण में भिन्नता– हालाँकि दोनों देश चीन की आक्रामकता को लेकर सजग हैं और क्वाड जैसे मंचों पर साथ काम कर रहे हैं, फिर भी भारत की सीमाओं पर चीन के साथ तनाव और अमेरिका की ताइवान नीति पर प्रतिक्रिया अलग-अलग रही है। यह अंतर दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण में मतभेद को दर्शाता है।

4. मानवाधिकार और आंतरिक नीतियों पर मतभेद– अमेरिका अक्सर भारत में मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकारों, मीडिया स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रताओं पर चिंता जताता रहा है। इससे भारत की संप्रभुता के दृष्टिकोण से असहजता उत्पन्न होती है और कूटनीतिक संवाद में अवरोध आ सकता है।

5. रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सीमाएँ– हालाँकि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नीति, रक्षा संवेदनशीलता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के कारण भारत को अभी भी आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

6. विकासशील देशों की प्राथमिकताएँ बनाम विकसित देशों की अपेक्षाएँ– जलवायु परिवर्तन, जैसे वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा को लेकर भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण में मतभेद रहे हैं। अमेरिका द्वारा उठाए गए जलवायु संबंधी कदम भारत पर प्रतिकूल दबाव डालते हैं, जबकि भारत हरित विकास के साथ ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करना चाहता है।

7. जनमत और राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव– दोनों देशों में शासन परिवर्तन और जनमत का असर रणनीतिक रिश्तों पर पड़ता है। भारत में अमेरिका की नीतियों को लेकर ऐतिहासिक संदेह और अमेरिका में भारत की घरेलू नीतियों को लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण, संबंधों में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं।

इन समकालीन चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों के नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि रणनीतिक साझेदारी को और गहरा बनाने की प्रतिबद्धता बनी हुई है। समस्याएँ अस्थायी हो सकती हैं, परन्तु उनके समाधान हेतु निरंतर संवाद और पारस्परिक समझ आवश्यक है।

समाधान– भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहराई व स्थायित्व प्रदान करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

उच्च-स्तरीय संवादों (2+2, QUAD, IPEF) की निरंतरता दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने में सहायक होगी। व्यापारिक बाधाओं जैसे टैरिफ, IP अधिकार, और सेवा क्षेत्र की प्रतिबंधित पहुंच को पारस्परिक रूप से सुलझाया जाए। उच्च शिक्षा, अनुसंधान व छात्रवृत्तियों के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने के लिए साझेदारी को बढ़ाया जाए। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हो। क्लाइमेट इनिशिएटिव, इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन हाइड्रोजन, व नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में संयुक्त निवेश किया जाए। महामारी से निपटने हेतु वैक्सीन अनुसंधान, स्वास्थ्य अवसंरचना, और WHO जैसे मंचों पर समन्वय किया जाए। मीडिया, फिल्म, साहित्य, और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ावा देना आवश्यक है। नौसेना अभ्यास, सामरिक सूचनाओं का आदान-प्रदान, व इंडो-पैसिफिक रणनीति में तालमेल बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष— भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी 21वीं सदी में विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। यह साझेदारी केवल पारंपरिक सुरक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऊर्जा, तकनीकी नवाचार, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा, और वैश्विक शासन जैसे विविध आयाम भी शामिल हैं। दोनों देशों की लोकतांत्रिक संस्थाएँ, बहुलतावादी समाज और वैश्विक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता, इस रिश्ते को दीर्घकालिक और भरोसेमंद बनाती हैं। समकालीन चुनौतियों के बावजूद, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में अपार संभावनाएँ हैं जो वैश्विक शक्ति-संतुलन को नए स्वरूप में परिभाषित कर सकती हैं।

सन्दर्भ सूची –

1. सिंह, सुरेन्द्र, भारत-अमेरिका संबंधों का इतिहास, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2020. ISBN: 9789385784179
2. शर्मा, अजय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत-अमेरिका संबंध, इलाहाबादरु विश्व पुस्तक भंडार, 2019. ISBN: 9788194009861
3. कौल, कुसुम लता। भारत की विदेश नीति, एक समकालीन विश्लेषण, भोपाल, ओम प्रकाशन, 2021. ISBN: 9789385729033
4. Foreign Policy of India: Emerging Trends – संपादक के. पी. मिश्रा, नई दिल्ली, मित्तल पब्लिकेशंस, 2018.
5. भारतीय रक्षा मंत्रालय। भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग रिपोर्ट, 2022.
6. गौतम, आर. एस. भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, एक विश्लेषण, दिल्ली, नीति प्रकाशन, 2017. ISBN: 9789383722555
7. नीति आयोग। भारत-अमेरिका तकनीकी और व्यापार सहयोग रिपोर्ट, 2023.
8. ज्योति, रेखा, भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध, एक आलोचनात्मक अध्ययन, बनारस, विद्या पब्लिशिंग, 2021.
9. MEA Archives, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय बैठकें और दस्तावेज़, 2020–2024.
- 10- Tellis, Ashley J. – India's Emerging Nuclear Posture, Carnegie Endowment, 2001, ISBN: 9780870031854
- 11- Pant, Harsh V. – India in the Indo-Pacific: Enhancing Cooperation with the United States, Routledge, 2020, ISBN: 9780367366254
- 12- Mohan, C. Raja – Crossing the Rubicon: The Shaping of India's New Foreign Policy, Viking, 2003, ISBN: 9780670049635
- 13- Kapila, Subhash – India's Strategic Environment: Dynamics of Security Policy, Manas Publications, 2006, ISBN: 8170492332

- 14- Singh, Swaran – India and the United States: A Relationship Revisited, Shipra, 2021, ISBN: 9788175419474
- 15- Tellis, Ashley J., et al. – Strategic Asia 2020: U.S.-China Competition, NBR, ISBN: 9781939130700
- 16- Kronstadt, K. Alan – U.S.-India Bilateral Issues, CRS Report for Congress, 2019
- 17- Muni, S.D. – India's Foreign Policy: The Democracy Dimension, Cambridge University Press, 2009
- 18- Raghavan, Srinath – War and Peace in Modern India, Palgrave Macmillan, 2010, ISBN: 9780230238007
- 19- Schaffer, Teresita C. – India and the U.S. in the 21st Century, CSIS Press, 2009, ISBN: 9780892065581